The House then adjourned for lunch at thirty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock, **(The Vice-Chairman Miss Saroj Khaparde)** in the Chair.

SPECIAL MENTIONS—contd.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): We will continue with Special Mentions. Shri S. S. Surjewala.

Exorbitant price and high maintenance cost of tractors

SHRI S. S. SURJEWALA (Haryana): Madam Vice-Chairman, I wanted to draw the attention of this House towards a very important problem being faced by the farmers with regard to tractors in the country, particularly of Northern India. Tractors which at one time had become a symbol of the Green Revolution in the North Indian States of Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh and Rajasthan is no longer considered a friend of the farmers and is increasingly becoming a white elephant. It is estimated that there are more than 5,00,000 tractors in the State, of Punjab and Haryana. The fact that small and lower middle class farmers are abandoning the tractors for various reasons is not only a matter of anxiety but it also reflects the helplessness of the poor peasantry. The exorbitant price of tractors being charged by the manufacturers is amounting to a loot and the high maintenance cost of these machines is forcing farmers to adopt the age-old system of using bullocks and camels for ploughing their lands and means of transportation.

The nationalised banks which were supposed to improve the living standards of the farming community has exploited the general illiteracy prevailing among the small and middle farmers. The banks lured farmers into obtaining loans at high rate of interest and in return mortgaging their small land holdings. Unaware of the compound interest rates and a large number of recovery suits filed in the civil courts by these banks, which led to the attachment and sale of their land, the farmers feel cheated at the hands of the banks.

A sharp increase in the cost of agriculture inputs, high maintenance cost of tractors, bank disputes and spurious diesel and lubricants are causing a heavy damage to the engines of the tractors. These things are forcing the farmers in the Northern States to abandon their tractors.

Unless and until the State Governments and the Union Government come to the rescue of the farmers and find a solution to the various problems this is going to cause a serious set-back to the food production programme in our country and will also reduce the size of the peasantry which helped the country in producing surplus foodgrains. They will also be forced to degradation. Thank you.

श्री इकबाल सिंह (पंजाब) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं भी इसके साथ एसोसियेट करता हूं । यह देखा गया है कि बैंक इतना ब्याज ले रहे हैं और इतना तंग कर रहे हैं और खास कर के पंजाब में मैंने देखा है कि मेंटेनेंस करना फारमर के लिए इतना कॉस्टली हो चुका है । इस लिए सदन को जरुर इसका ध्याल रखना चाहिये ताकि इसको साल्व किया जा सके ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : धन्यवाद ।

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1994-95

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): Madam, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (Railways) for the year 1994-95.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, we shall take up further discussion on the Gö-

vernment Resolution on the National Housing Policy. Shri Ish Rutt Yadav to continue.

GOVERNMENT RESOLUTION ON NATIONAL POLICY CONTD.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : मैडम, कल भी मैंने कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि यह राष्ट्रीय आवास नीति का जो दस्तावेज है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें इस देश की आवास की समस्या हल होने वाली नहीं है । यह दस्तावेज मुझे बिलकुल निरर्थक सा लग रहा है । जब हम लोग विपक्ष में थे, अब भी हैं, जब कभी यह लोग विपक्ष में थे तो बहुत नारे लगाए जाते हैं । उनमें से एक नारा हमेशा लगता है, जो विपक्ष में रहता है :

रोटी कपड़ा और मकान,
मांग रहा भूखा, नंगा इन्सान ।

महोदया, हमें आजाद हुए 46 साल हो चुके हैं और 40 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है केन्द्र में भी अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी का राज रहा लेकिन आज तक आवास समस्या हल नहीं हो सकी । उस पर विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं । मैडम, सन् 1988 में राष्ट्र संघ ने एक आवास नीति का मसौदा तैयार किया था और सभी सदस्य देशों को इसे प्रेषित किया था । सभी सदस्य देशों ने इसके लिए स्वीकृति दी थी । 1988 में ही अपने देश में लोक सभा और राज्य सभा में इस आवास नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया था । जहां तक मेरी जानकारी है राज्य सभा ने भी अपनी स्वीकृति दे दी थी । लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा माननीय शहरी विकास मंत्री जी से कि 6 वर्ष बीत गये, आपने जो मसौदा पेश किया था जिसकी स्वीकृति भी राज्य सभा से हुई थी, आज तक उसको कितना आपने कार्यान्वित किया और कितनी इसमें आपको सफलता मिली है, कितने आवासों का निर्माण आपकी इस नीति के चलते हुआ ? यह 1988 में भी केवल आपने यह कोरा नारा दिया था और आज भी आपकी स्थिति वही है ।

मैडम, नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जिसका उल्लेख नेशनल हाऊसिंग पालिसी में किया गया है, इस नेशन बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन की सन् 1991 की रिपोर्ट के हिसाब से 31 मिलियन यूनिट्स मकानों की आवश्यकता है । जो रिपोर्ट में 20.6 मिलियन यूनिट्स देहात में, गांवों में और 10.4 मिलियन यूनिट् शहरों में आवश्यकता है । मैं समझता हूं आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार का यही लक्ष्य है ।

यद्यपि कि मैं इस रिपोर्ट को सही नहीं मानता हूं । यह बिल्कुल सही रिपोर्ट नहीं है इतने बड़े देश के लिए । सरकार तो आंकड़ों पर चलती है । वास्तविक स्थिति की तो सरकार को जानकारी नहीं है । मंत्री जी लोग कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं करते जनता की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए । इनके जो अधिकारी होते हैं वे गांवों को जानते ही नहीं कि कहां गांव होता है क्या उसकी स्थिति होती है । अपने एयर कंडीशन्स कमरों में बैठकर फर्जी आंकड़े तैयार कर देते हैं । मैं इन आंकड़ों को सही नहीं मानता हूं जो नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन ने दिए हैं । मैडम, अगर इन्हीं आंकड़ों को सही मान लिया जाए जिनका उल्लेख नेशनल हाउसिंग पालिसी में किया गया है—यदि देश की आबादी इसी गति में बढ़ती रही तो माननीय मंत्री जी को मैं सावधान करना चाहता हूं कि सौ साल में आपकी स्कीम पूरी नहीं होगी, और सौ साल बीत जाएंगे । सौ साल में भी चाहे गांव में कोई रहने वाला हो या शहर में हो उसके मकान की समस्या आप हल नहीं कर पाएंगे । इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीया मंत्री जी से कि बहुत कुछ ठोस कदम उठाइये । इस तरह के दस्तावेजों से जो काम के कम लगते हैं और आदर्श तथा उपदेश के दस्तावेज ज्यादा लगते हैं, इनसे कोई काम नहीं चलने वाला है ।

मैडम, आज आवास की जो समस्या इस देश की है, यह बहुत जटिल समस्या है । आम आदमी के जीवन से, उसके अच्छे जीवन से, उसके सुखमय जीवन से, उसके लम्बे जीवन से उसकी प्रगति से आवास की समस्या जुड़ी हुई है । मैडम, माननीया